



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1795]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 20, 2019/ज्येष्ठ 30, 1941

No. 1795]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 20, 2019/JYAISTHA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2019

(आयकर विभाग)

का.आ. 2007 (अ).— जबकि केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (इसके पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से सन्दर्भित किया गया है) की धारा 80 झक की उप धारा (4) के खण्ड (iii) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचनाएं संख्या का. आ. 354(अ) दिनांक 01 अप्रैल, 2002 द्वारा 1 अप्रैल, 1997 से शुरू और 31 मार्च, 2006 को समाप्त अवधि के लिए औद्योगिक(इंडस्ट्रियल) पार्क हेतु योजना को तैयार और अधिसूचित किया है;

और जबकि मैसर्स मगरथ प्रोपर्टीज प्रा. लि. जिसका पंजीकृत(रजिस्टर्ड) कार्यालय प्रथम तल, एक्वेसी प्वाइन्ट, 150 इन्फेंट्री रोड, बंगलौर-560001 है, ने सर्वे न.13/2 चाल्लाघटा गाँव, वरथुर होबली, बंगलौर, कर्नाटक-560001 में औद्योगिक पार्क को विकसित किया है।

और जबकि केन्द्र सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के पत्र संख्या 15/177/2005-आईपी एवं आईडी दिनांक 25/7/2006 द्वारा उक्त औद्योगिक पार्क को अनुमोदित किया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 80 झक की उप धारा (4) के खण्ड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त खण्ड (iii) के प्रयोजनार्थ अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के अधीन उपक्रम को एक औद्योगिक पार्क के रूप में, जिसे मैसर्स मगरथ प्रोपर्टीज प्रा.लि. द्वारा विकसित, देखरेख और संचालित किया जा रहा है, को अधिसूचित करती है।

अनुबंध

वे निबंधन और शर्तें, जिनके आधार पर भारत सरकार ने मैसर्स मगरथ प्रोपर्टीज प्रा.लि. द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना करने के लिए अपना अनुमोदन दिया है।

- (i) औद्योगिक पार्क का नाम : मैसर्स मगरथ प्रोपर्टीज प्रा.लि.
 (ii) प्रस्तावित स्थान : सर्वे न. 13/2, चाल्लाघटा गाँव वरथुर होबली, बंगलौर, कनार्टक-560001
 (iii) औद्योगिक पार्क का क्षेत्र : 24, 636.00 वर्ग-मीटर
 (iv) प्रस्तावित कार्यकलाप : एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक कार्यकलाप का स्वरूप एनआईसी कोड विवरण

क्र.सं.	अनुभाग	प्रभाग	समूह	श्रेणी	
क	8	89	892	-	डाटा प्रोसेसिंग, साफ्टवेयर तैयार करना और कम्प्यूटर परामर्शी सेवाएं।
ख	8	89	893	-	कारोबार और प्रबंधन परामर्शी कार्यकलाप।
ग	8	89	894	-	वास्तुशिल्पीय और इंजीनियरिंग तथा अन्य तकनीकी परामर्शी कलाप।

- (v) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित : 92.32% आवंटन योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
 (vi) वाणिज्यिक उपयोग के लिए आवंटन : 7.68% योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
 (vii) औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या : 04 इकाइयां(यूनिट)
 (viii) प्रस्तावित कुल निवेश(राशि रु. में) : 47.78 करोड़ रु.
 (ix) औद्योगिक उपयोग हेतु निर्मित स्थान पर निवेश : 14.88 करोड़ रु. (राशि रु. में)
 (x) औद्योगिक उपयोग हेतु निर्मित स्थान पर निवेश : 41.76 करोड़ रु. सहित अवसंरचना विकास पर निवेश (राशि रु. में)
 (xi) औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित : सितम्बर, 2004 तारीख

2. औद्योगिक पार्क में अवसंरचना विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत के 50 प्रतिशत से कम नहीं होगा। यदि औद्योगिक पार्क औद्योगिक प्रयोग हेतु निर्मित स्थान प्रदान करता है, तब औद्योगिक स्थान की निर्माण लागत सहित अवसंरचना विकास पर न्यूनतम व्यय कुल परियोजना लागत के 60 प्रतिशत से कम नहीं होगा।

3. अवसंरचना विकास में रोड (पहुंच(एप्रोच) रोड सहित), जल आपूर्ति और सीवरेज, सामान्य बहिःस्राव संसाधन/शोधन सुविधा, टेलिकॉम नेटवर्क, विद्युत का सृजन और वितरण, एयरकन्डिशनिंग और ऐसी अन्य सुविधाएं शामिल होंगी जोकि औद्योगिक कार्यकलाप के लिए सामान्य प्रयोग की हैं जोकि ज्ञात योग्य हैं और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं।

4. का.आ. 354(अ) दिनांक 01 अप्रैल, 2002 के पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (ख) में दी गई तालिका के कॉलम (2) में सन्दर्भित कोई भी एकल इकाई औद्योगिक पार्क के आवंटन योग्य औद्योगिक क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक स्थान नहीं घेरेगी। इस उद्देश्य के लिए किसी इकाई का अर्थ किसी एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए अलग और विशिष्ट सत्ता (एन्टिटी) से है।

5. प्रवृत्त कानून के तहत विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या निर्दिष्ट किसी प्राधिकरण द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या अनिवासी भारतीय निवेश सहित आवश्यक अनुमोदनों को प्रवृत्त नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा।

6. अधिनियम के तहत कर का लाभ केवल तभी मिलेगा जब इस अधिसूचना के पैरा 1(vii) में इंगित यूनिटों की संख्या औद्योगिक पार्क में स्थित हों।

7. मैसर्स मगरथ प्रोपर्टीज प्रा. लि. उस अवधि के दौरान जिसमें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झक की उप धारा (4) के खण्ड (iii) के तहत लाभों को प्राप्त किया जाना है, औद्योगिक पार्क का संचालन करना जारी रखेगा।

8. यदि औद्योगिक पार्क 31/3/2006 तक प्रारंभ नहीं हुआ तब औद्योगिक पार्क योजना, 2008 के तहत नया अनुमोदन अपेक्षित होगा जोकि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 झ क की उप धारा 4(iii) के तहत लाभों को प्राप्त करने के लिए योजना के तहत प्रयोजनीयता की शर्त के अधीन होगा।
9. अनुमोदन अवैध हो जाएगा और मैसर्स मगरथ प्रोपर्टीज प्रा.लि. इस प्रकार की अवैधता के परिणामों के प्रति स्वयं ही उत्तरदायी होगा, यदि
- (i) उस प्रयोग में, जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने अपना अनुमोदन दिया है, गलत सूचना या छद्म सूचना दी गई हो या कुछ ऐसी सूचना जो इसमें प्रदान नहीं की गई हैं।
- (ii) यह उस औद्योगिक पार्क की अवस्थिति के बारे में है जिसके लिए किसी अन्य उपक्रम के नाम से पहले ही अनुमोदन जारी किया गया है।
10. यदि मगरथ प्रोपर्टीज प्रा.लि. औद्योगिक पार्क(अर्थात् अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव को दूसरे उपक्रम(अर्थात् अंतरिती उपक्रम) को अन्तरित करता है, तब अंतरणकर्ता और अंतरिती संयुक्त रूप से औद्योगिक सहायता सचिवालय की उद्यमियता सहायता यूनिट, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, उद्योग भावन, नई दिल्ली-110001 को सूचित करेंगे व इसके साथ उपर्युक्त अन्तरण के लिए अंतरणकर्ता और अंतरिती के बीच निष्पादित समझौते की प्रति भी होगी।
11. इस अधिसूचना में उल्लिखित निबंधन और शर्तों के साथ-साथ उन शर्तों जोकि उपर्युक्त औद्योगिक पार्क योजना, 2002 में शामिल की गई हैं, उस अवधि के दौरान अनुपालन किया जाएगा जिस अवधि के लिए उक्त योजना के अंतर्गत लाभ लिया जाना है और यदि मैसर्स मगरथ प्रोपर्टीज प्रा. लि. किसी भी शर्त को पूरा करने में असफल रहता है तो केंद्र सरकार उपर्युक्त अनुमोदन को वापस ले सकती है।
12. यदि केंद्र सरकार के अनुमोदन के बिना प्रक्षेपित योजना में कोई संशोधन होता है या किसी ऐसे संशोधन का भविष्य में पता चलता है या यह उपक्रम किसी सारवान तथ्य को प्रकट करने में चूक करता है तो इससे औद्योगिक पार्क का अनुमोदन रद्द हो जाएगा।

[अधिसूचना सं. 47/2019, फा. सं. 178/47/2017-आईटीए-1]

राजाराजेश्वरी आर. अवर सचिव,

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION
 New Delhi, the 20th June, 2019
(INCOME-TAX)

S.O. 2007(E).—Whereas the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of Section 80-IA of the Income-tax Act, 1961(43 of 1961)(hereinafter referred to as the said Act), has framed and notified a scheme for industrial park, by the notifications of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) vide number S.O. 354(E), dated the 1st day of April, 2002, for the period beginning on the 1st day of April, 1997 and ending on the 31st day of March, 2006;

And whereas M/s. Magrath Properties Pvt. Ltd. having its registered office at First Floor, Embassy Point, 150, Infantry Road, Bangalore-560001 has developed an industrial park located at Survey No. 13/2, Challaghata Village, Varthur Hobli, Bangalore, Karnataka- 560001.

And whereas the Central Government has approved the said Industrial Park vide Ministry of Commerce and Industry letter No. 15/177/2005-IP&ID dated 25-07-2006.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the said Act, the Central Government hereby notifies the undertaking, being developed and being maintained and operated by M/s. Magrath Properties Pvt. Ltd., as an industrial park for the purposes of the said clause (iii) subject to the terms and conditions mentioned in the annexure of the notification.

ANNEXURE

The terms and conditions on which the approval of the Government of India has been accorded for setting up of an industrial park by M/s Magrath Properties Pvt. Ltd.

- (i) Name of the Industrial park : M/s Magrath Properties Pvt. Ltd.
- (ii) Proposed location : Survey No. 13/2, Challaghata Village, Varthur Hobli, Bangalore, Karnataka- 560001.
- (iii) Area of Industrial Park : 24,636.00 square meters.
- (iv) Proposed Activates :

Nature of Industrial activity with NIC code				
		NIC Code		Description
S. No.	Section	Division	Group	Class
A	8	89	892	- Data processing, software development and computer consultancy services
B	8	89	893	- Business and management Consultancy activity
C	8	89	894	- Architectural and engineering and other technical consultancy activities.

- (v) Percentage of allocable, area : 92.32%
earmarked for industrial use
- (vi) Percentage of allocable area : 7.68%
earmarked for commercial use
- (vii) Minimum number of industrial units : 04 units
- (viii) Total investments proposed (Amount : Rs. 47.78 crore
in Rupees) : Rs. 14.88 crore
- (ix) Investment on built up space for
Industrial use (Amount in Rupees)
- (x) Investment on Infrastructure
Development including investment : Rs. 41.76 crore
on built up space for industrial use
(Amount in Rupees)
- (xi) Proposed date of commencement of
the Industrial Park : September 2004

2. The minimum investment on infrastructure development in an Industrial Park shall not be less than 50% of the total project cost. In the case of an Industrial Park which provides built-up space for industrial use, the minimum expenditure on infrastructure development including cost of construction of industrial space, shall not be less than 60% of the total project cost.

3. Infrastructure development shall include, roads (including approach roads), water supply and sewerage, common effluent treatment facility, telecom network, generation and distribution of power, air-conditioning and such other facilities as are for common use for industrial activity which are identifiable and are provided on commercial terms.

4. No single unit referred to in column (2) of the Table given in sub-paragraph (b) of paragraph 6 of S.O. 354(E) dated the 1st April, 2002, shall occupy more than fifty per cent of the allocable industrial area of an Industrial Park. For this purpose a unit means any separate and distinct entity for the purpose of one and more state or Central tax laws.

5. Necessary approvals, including that for foreign direct investment or non-resident Indian investment by the Foreign Investment Promotion Board or Reserve Bank of India or any authority specified under any law for the time being in force, shall be taken separately as per the policy and procedures in force.

6. The tax benefits under the Act can be availed of only after the number of units indicated in Para 1 (vii) of this Notification, are located in the industrial Park.

7. M/s. Magrath Properties Pvt. Ltd., shall continue to operate the Industrial Park during the period in which the benefits under clause (iii) of sub-section (4) of section 80-IA of the Income-tax Act, 1961 are to be availed.

8. In case the Industrial Park did not commence by 31-3-2006, fresh approval will be required under the Industrial Park Scheme, 2008 subject to the applicability under that Scheme for availing benefits under sub-section 4(iii) of Section 80- IA of the Income Tax Act, 1961.

9. The approval will be invalid and M/s. Magrath Properties Pvt. Ltd., shall be solely responsible for any repercussions of such invalidity, if

(i) the application on the basis of which the approval is accorded by the Central Government contains wrong information/misinformation or some material information has not been provided in it.

(ii) it is for the location of the industrial park for which approval has already been accorded in the name of another undertaking.

10. In case M/s. Magrath Properties Pvt. Ltd., transfers the operation and maintenance of the industrial park (i.e., transferor undertaking) to another undertaking (i.e., the transferee undertaking), the transferor and transferee shall jointly intimate to the Entrepreneurial Assistance Unit of the Secretariat for Industrial Assistance, Department of Industrial Policy and Promotion, Udyog Bhawan, New Delhi-110001 along with a copy of the agreement executed between the transferor and transferee undertaking for the aforesaid transfer.

11. The conditions mentioned in this notification as well as those included in the Industrial Park Scheme, 2002 should be adhered to during the period for which benefits under this scheme are to be availed. The Central Government may withdraw the above approval in case M/s. Magrath Properties Pvt. Ltd., fails to comply with any of the conditions.

12. Any amendment of the project plan without the approval of the Central Government or detection in future or failure on the part of the applicant to disclose any material fact, will invalidate the approval of the industrial park.

[Notification No. 47/2019/ F. No. 178/47/2017-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.